बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 72

हकीकत से दूर

देश के सबसे बड़े और कटुता से भरे हुए आम चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश लोगों ने यह उम्मीद की होगी कि इन अंतिम कुछ सप्ताह में मतदाताओं के समक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां प्रस्तुत की जाएंगी, भविष्य को लेकर उसके वादे सामने रखे जाएंगे और विपक्ष अपनी ओर से विकल्प की पेशकश करेगा। प्रचार अभियान की शुरुआत इसी तर्ज पर हुई। भाजपा ने 'नामुमकिन अब मुमकिन है' का नारा दिया। राहुल गांधी ने न्याय योजना प्रस्तुत की और मजबूत सरकार और गठबंधन सरकार के संभावित लाभ और हानि पर चर्चा हुई। परंतु ऐसा लगता है कि कम ही लोगों ने न्याय के बारे में सुना है जबकि विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। भाजपा को संभवत: यह अहसास हुआ कि उसका विकास संबंधी प्रदर्शन उतना उत्साहजनक नहीं है। उसने पुलवामा हमले और बालाकोट में की गई बदले की कार्रवाई को एजेंडा बनाया और पूरी बहस राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर मोड़ दी। यही वह वक्त था जब हकीकत और प्रचार अभियान में अंतर पैदा होने लगा। मोदी की खासियत है कि वह अपनी कमजोरियों को खूबी में बदल देते हैं। यह देखने को भी मिला। चौकीदार सेना पर आतंकी हमले को लेकर मिल रही खुफिया विभाग की चेतावनियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा, एक लड़ाकू विमान को मार गिराने से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, इससे भी बुरी बात कि एक हेलीकॉप्टर अपने ही हमले में मार गिराया गया, यह सच सामने आया कि भारतीय वायुसेना की तुलना में अत्यंत मामूली बजट से संचालित पाकिस्तानी वायुसेना के पास बेहतर लड़ाकू विमान और बेहतर मिसाइलें तो हैं ही, उसका संचार लिंक भी हमसे अधिक सुरक्षित है। इन तमाम असहज करने वाली हकीकतों को एक तेजतर्रार अभियान के नीचे दबा दिया गया। यह अभियान दो बातों पर केंद्रित था: बालाकोट हमला और मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवाना। कांग्रेस ने बहुत देर से यह घोषणा शुरू की कि उसने भी सर्जिकल स्ट्राइक समेत अन्य सफलताएं हासिल की हैं लेकिन वह हमेशा की तरह डरपोक साबित कर दी गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को एक अन्य दिलचस्प मोड़ देते हुए कहा गया कि इस बात का खतरा है कि देशद्रोहियों का 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' देश को तोड़ सकता है। राष्ट्रवादियों को अपने मुल्क की ताकत में कहीं ज्यादा भरोसा होना चाहिए था। अगर कोई खतरा है भी तो इससे निपटने की सरकार की नीति क्या है? नक्सल प्रभावित इलाकों और जम्मू और कश्मीर में हिंसा का बढ़ता स्तर नीतिगत नाकामी को दर्शाता है। चीन की ओर से सुरक्षा को जो चुनौती मिल रही है, उसका उल्लेख तक नहीं है जबकि चीन हमारे पड़ोस में पहुंच रहा है। अब पूरी चर्चा हास्यास्पद स्तर तक गिर चुकी है। एक ऐसे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका निधन हुए चौथाई सदी बीत चुकी है। इससे पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री के कदमों पर सवाल उठाया जा रहा था जो 50 वर्ष से भी अधिक पहले गुजर गए। नेहरू और राजीव गांधी की जो भी गलतियां या चूक रही हों, क्या वे 2019 के चुनाव में मुद्दा हैं या फिर यह जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है?

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

यह ध्यान रहे कि भाजपा ने अर्थव्यवस्था की बात ही नहीं की है। बार-बार यही इल्जाम लगाया जाता रहा है कि मोदी के आने से पहले के 70 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस निष्प्रभावी तरीके से वृद्धि में धीमापन आने, निर्यात में ठहराव और निवेश में कमी का जिक्र करती है। आंकड़ों से छेड़छाड़ का मसला भी हाल में उठा है। रोजगार और ग्रामीण संकट को लेकर काफी कुछ कहा गया लेकिन मोदी ने अब तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ये बातें मतदाताओं के लिए कितनी अहम हैं? दलगत राजनीति में लोग ऐसे तथ्य चुनते हैं जो उनके पूर्वग्रह या उनकी मान्यता पर सटीक बैठते हों, खासकर तब जब एक मजबूत नेता सामने हो। लाखों लोगों के लिए मोदी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ भले नहीं हो लेकिन वह उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतर हैं। या कहें लोगों को उनका हिंदूवादी राष्ट्रवाद रास आया है। इस बीच मोदी ने एक बार फिर यह दर्शाया है कि कैसे वह अपने आलोचकों की बाजी पलट सकते हैं। उन्होंने उन अपशब्दों का जिक्र किया जो बीते सालों के दौरान उन्हें कहे गए। उन्होंने तंज भरे लहजे में राहुल गांधी की 'लव डिक्शनरी' का जिक्र किया। इस अभियान के दौरान एक बात स्पष्ट हो गई कि मोदी किसी भी विकेट पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंद को सीमारेखा के पार पहुंचा सकते हैं। इस काम में वे तथ्यों का चुनिंदा इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और आलंकारिक शैली में नामदार और कामदार का जिक्र करते हैं।

चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि उनकी पार्टी बहुमत गंवा सकती है और उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम होगी। अगर ऐसा हुआ तो यह विपक्ष के कारण कम और उनकी वजह से अधिक होगा क्योंकि पांच साल तक छवि निर्माण, आक्रामक सोशल मीडिया ट्रोलिंग और नाटकीय अंदाज में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद हिंदी प्रदेश के मतदाता उनके प्रदर्शन से निराश हैं।

विनय सिन्हा

आईआईटी रुड़की और जेम्स थॉमसन

आईआईटी रुड़की की यात्रा से औपनिवेशिक युग के एक ऐसे इंजीनियर के बारे में पता चला जिनके नाम पर एक शैक्षणिक संस्थान और एक रेल इंजन दोनों हैं। जानकारी प्रदान कर रहे हैं **विवेक देवराय**

हाल ही में मैं कुछ परिचर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए आईआईटी रुड़की गया था। रुड़की कॉलेज को आईआईटी रुड़की का पूर्ववर्ती माना जा सकता है। वहां मुझे एक विशेष लेख देखने को मिला, जो सन 1851 में प्रकाशित हुआ था। उस लेख का शीर्षक था, 'रुड़की कॉलेज का लेखा, जिसकी स्थापना सिविल इंजीनियरों के निर्देशन हेतु की गई, इसकी विस्तार योजना भी साथ ही बनी।'

देश में सिविल इंजीनियरों के व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

पश्चिमी यमुना नहर की शुरुआत सन 1817 में हुई। पूर्वी यमुना नहर की शुरुआत सन 1822 में हुई।

देहरादून में, रुहेलखंड में और दिल्ली के निकट नजफगढ़ में सरकार ही लंबे समय से नालियों और सिंचाई आदि का काम संभाल रही थी।

पिछले 20 या 30 वर्ष में सरकार ने अपने खर्च पर कई बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया है। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तात्कालिक उपाय करने आवश्यक थे। बेहतर प्रशिक्षण वाले अनुभवी सिविल इंजीनियरों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी यह आवश्यक था। इन इंजीनियरों की ऐसी तैयारी आवश्यक थी जिसकी बदौलत वे उन कठिनाइयों से जूझ सकें जो बेहतर प्रबंधन की राह में सामने आतीं। कहने का तात्पर्य यह है कि रुड़की कॉलेज की स्थापना ऐसी ही आपातकालीन परिस्थितियों में हुई। यह कॉलेज 25 नवंबर 1847 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। गजेटियर से हमें यह भी पता चला कि अनौपचारिक तौर एक कक्षा 1845 में ही शुरू हो गई थी, जहां स्थानीय युवाओं को इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। यह शुरुआत थी। जेम्स थॉमसन पश्चिमोत्तर प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। यही कारण है कि उनके निधन के बाद रुड़की कॉलेज को थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। बाद में यह आईआईटी रुड़की बन गया और इसके प्रमुख प्रशासनिक भवन को थॉमसन भवन का नाम दिया गया।

आश्चर्य नहीं कि वहां मेरी मुलाकात जिन छात्रों से हुई, उनको इस इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि उनको उस प्रस्तावित विस्तार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, जिसका उल्लेख सन 1851 के आलेख में था। उसमें रुड़की से 40-50 मील के दायरे में आने वाले गांवों के विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने की बात शामिल थी। योजना यह थी कि कुछ आदर्श ग्रामीण विद्यालय स्थापित किए जाएं और आगंतुकों के लिए एक प्रतिष्ठान बनाया जाए जिनका काम होगा उनको आवंटित गांवों में जाना तथा वहां के विद्यालयों का स्तर आंकना तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों को सलाह देना और उनकी सहायता करना। इस काम में निर्देशन, पुस्तकों और पुरस्कार आदि का इस्तेमाल किया जाना तय हुआ था।

सन 1935 में लेफ्टिनेंट कर्नल ई.डब्ल्यू.सी. सैंड्स की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था- द मिलिट्री इंजीनियर इन इंडिया। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने रुड़की कॉलेज को देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज बताया। उन्होंने लिखा कि रुड़की का थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज दरअसल सबसे पुराना है और यह भारत में अपनी तरह का अनूठा कॉलेज है।

उन्होंने लिखा कि थॉमसन कॉलेज अपने अस्तित्व के लिए गंगा नदी का ऋणी है क्योंकि इस पवित्र नदी के बगैर न तो गंग नहर होती और न ही बिना नहर के यह कॉलेज अस्तित्व में आता।

हालांकि यह अपने आप में बहस का विषय है क्योंकि चेन्नई स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सन 1859 में औपचारिक रूप से कॉलेज बना जबकि उसके पहले सन 1794 में ही स्कूल ऑफ सर्वे की स्थापना की जा चुकी थी। परंतु जेम्स थॉमसन की विशिष्टता के बारे में कहीं किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। मुझे ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके नाम पर शैक्षणिक संस्थान भी हो और रेल इंजन भी। कर्नल प्रॉबी टी कॉटली वह इंजीनियर थे, जिन्होंने गंग नहर के निर्माण की निगरानी की। उन्होंने इस नहर के निर्माण कार्य पर एक रिपोर्ट भी लिखी। अपनी इस रिपोर्ट में वह कहते हैं, 'रेलमार्ग और वैगन के निर्माण से हमें व्हील बैरो और बास्केट से राहत मिली, लेकिन काफी लंबे समय तक हमारा मानव संसाधन खुदाई और वैगनों को धकेलने के काम में भी लगा।'

'समय बीतने के साथ कुछ स्थानों पर मनुष्य का स्थान घोड़े ने लिया। 22 दिसंबर 1851 को रेल इंजन की शुरुआत हुई। मेरा मानना है कि भारत में इस्तेमाल किया गया वह अपनी तरह का अनूठा इंजन था।'

उनकी यह बात सही है क्योंकि आयातित भाप इंजन भारत में इस्तेमाल किया गया पहला रेल इंजन था। रुड़की रेलवे स्टेशन पर इसका एक मॉडल मौजूद है जो परिचालन योग्य है। उस वक्त जेनी लिंड किसी ओपरा गायक की तरह मशहूर थीं। वह अपनी ख्याति के शिखर पर थीं।

ऐसे में इस इंजन को शुरुआत में जेनी लिंड के नाम से जाना जाता था और यह रुड़की और पीर कलियर के बीच निर्माण सामग्री ढोने का काम करता था। जेनी लिंड को लंदन में प्रसिद्धि हासिल थी, थॉमसन पूर्वोत्तर प्रांत में ख्यात थे। यही कारण था कि इस इंजन का नाम बदलकर थॉमसन कर दिया गया। दुर्भाग्यवश 1852 में बॉयलर में विस्फोट हो गया और थॉमसन इंजन नहीं बच सका।

रिचर्ड बेयर्ड नामक एक इंजीनियर रुड़की में गंग नहर के कामकाज के प्रभारी हुआ करते थे। सन 1857 में उनसे कहा गया कि वह मुख्य इंजीनियर के रूप में दिल्ली जाएं। कर्नल वाइबर्ट ने अपनी पुस्तक में रिचर्ड बेयर्ड स्मिथ को सन 1857 में दिल्ली के नायकों के नेता के रूप में याद किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली जाने से पहले रुड़की में खंदक खोदने वाले सिपाहियों की दो कंपनियां मजबूती के बजाय कमजोरी का सबब बनीं। उनमें शामिल तमाम सिपाही स्थानीय थे। उनमें काफी हद तक असहजता का भाव था जिसने प्रदर्शन को प्रभावित किया। बेयर्ड ने उनको दो ऐसे अधिकारियों के अधीन रखा जो एक दूसरे से परिचित भी थे और उपलब्ध अधिकारियों में सबसे उत्कृष्ट भी थे। उन्होंने थॉमसन कॉलेज की इमारतों की देखरेख का काम भी उनको ही सौंपा।

(लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं)

समाचारपत्रों की लोकप्रियता और विश्वसनीयता बरकरार

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

सबसे पहले अच्छी खबर। वर्ष 2019 की पहली तिमाही में 42.5 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने समाचार पत्र पढ़े। यह तादाद वर्ष 2017 की पहली तिमाही के 40.7 करोड़ लोगों से अधिक है। यह आंकड़े इंडियन रीडरशिप सर्वे (आईआरएस) 2019 ने अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किए। दुनिया के अधिकांश बाजारों के उलट भारत में समाचार पत्रों के पाठकों की तादाद और उनका प्रसार बीते दशक में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2016 के अंत तक अगर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के 10 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो औसत प्रसार 4.87 फीसदी बढ़कर 6.3 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया। प्रिंट मीडिया 1,67,400 करोड़ रुपये के कारोबार वाले मीडिया और मनोरंजन उद्योग का सबसे अधिक मुनाफे वाला क्षेत्र बना रहा।

प्रश्न यह है कि बीते तीन वर्ष से उसका राजस्व ठहरा हुआ क्यों है? यहां पर अवश्य चिंतित होने की बात है। वर्ष 2018 तक के 10 वर्ष में मीडिया के कुल राजस्व में प्रिंट की हिस्सेदारी 30 फीसदी से घटकर 18 फीसदी से थोड़ी ज्यादा रह गई है। चूंकि इसका आधार बढ़ रहा था इसलिए वास्तव में देखें तो प्रिंट मीडिया का आकार करीब दोगुना हो गया। परंतु इन 10 वर्षों में से बीते तीन वर्ष वास्तव में कठिन रहे। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016 के 30,330 करोड़ रुपये (विज्ञापन एवं सब्सक्रिप्शन) से बढ़कर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का राजस्व 2018 तक केवल 30,550 करोड़ रुपये तक ही पहुंचा। दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह इंटरनेट कतई नहीं रहा है। बल्कि इसके लिए काफी हद तक यह उद्योग स्वयं जिम्मेदार रहा।

सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाठकों की संख्या पर आती है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापनों के लिए निर्धारित स्थान, इस उद्योग के 70 फीसदी राजस्व के लिए उत्तरदायी होता है। वर्ष 2013 से 2017 तक चार वर्ष की अवधि में प्रकाशकों ने जमकर कमाई की और उसके बाद वे इस राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की जद्दोजहद में लगे रहे। उस दौर में आंकड़ों की इस कदर उपलब्धता नहीं थी और विज्ञापनदाताओं ने अपनी राशि अन्य मीडिया माध्यमों में व्यय करनी शुरू कर दी। इसमें डिजिटल मीडिया भी शामिल है। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर के प्रिंट मीडिया उद्योग पर बुरे असर के बावजूद यह सिलसिला जारी रहा। रिलायंस ने जियो की शुरुआत की और डेटा कीमतें औंधे मुंह गिर पड़ी। इस कारण डेटा खपत में इजाफा हुआ। वर्ष 2016 में जहां प्रति व्यक्ति प्रति माह 0.8 जीबी डेटा खपत होती थी वहीं 2018 में यह बढ़कर 8 जीबी प्रति व्यक्ति प्रति माह हो गई।

इसे दूसरी तरह से देखें तो एक फिल्म एक जीबी डेटा लेती है। यानी करीब 5.5 करोड़ भारतीय ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हर महीने कम से कम 8 फिल्म डाउनलोड करने के बराबर डेटा इस्तेमाल करते हैं। डाउनलोड की जाने वाली सामग्री में फिल्म, टीवी शो, खेल या समाचार के कार्यक्रम कुछ भी हो सकती है। कुछ ओटीटी या वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के पास फिलहाल 10 से 20 करोड़ उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ताओं के पास ध्यान बांटने के लिए 2013 की तुलना में कहीं अधिक उपाय मौजूद हैं।

वर्ष 2018 में जब सबको स्वीकार्य आईआरएस आंकड़े सामने आए तब तक संभवत: बहुत अधिक देर हो चुकी थी। विज्ञापनों से मिलने वाले राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। विज्ञापन से जुड़े लोगों का कहना है कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आईआरएस कुल पाठक संख्या की बात करता है बजाय कि औसत पाठक संख्या के। औसत पाठक संख्या में बहुत अधिक इजाफा नहीं हुआ है। विज्ञापनदाता अभी भी औसत पाठक संख्या के आधार पर ही विज्ञापन के लिए स्थान खरीदते हैं।

आप यह दलील दे सकते हैं कि विज्ञापनदाता काफी हद तक ऐसे मानक इस्तेमाल करने में रुचि रखते हैं जिनके चलते कम दर पर विज्ञापन दिए जा सकें। फिर चाहे मामला टेलीविजन पर प्रति रेटिंग प्वाइंट लागत की हो या प्रिंट में एआईआर की। इसके अलावा एआईआर सभी विज्ञापनदाताओं के लिए काम नहीं करता। लंबी अवधि के दौरान ब्रांड तैयार करने के लक्ष्य की दृष्टि से समग्र पाठक संख्या बेहतर विकल्प है। अधिकांश प्रकाशक और विज्ञापनदाता इस बात से परिचित होते हैं। मानक के नहीं होने से उनको यह अवसर मिल जाता है कि वे दरों को कम रखें। वे ऐसा चाहते भी हैं।

कुल पाठक संख्या में हो रहा इजाफा और ऑनलाइन में आ रही उछाल उम्मीद बंधाती है। आईआरएस 2019 के अनुसार करीब 5.4 करोड़ लोग ऑनलाइन समाचार पत्र पढ़ते हैं। कॉमस्कोर जो डिजिटल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके मुताबिक करीब 27.9 करोड़ लोग ऑनलाइन समाचार पत्र पढ़ते हैं। देश के शीर्ष 20 ऑनलाइन प्रकाशकों में से 11 मुख्य धारा के मीडिया संस्थान हैं। उदाहरण के लिए टाइम्स इंटरनेट, एचटी मीडिया, इंडिया टुडे समूह और इंडियन एक्सप्रेस समूह आदि। प्रकाशक डिजिटल माध्यम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। मैंने हाल ही में ऑनलाइन राजस्व और मुनाफे के आंकड़ों का विश्लेषण किया और ये दोनों ही काफी बेहतर नजर आए। डिजिटल क्षेत्र के सब्सक्रिप्शन के शुरुआती रुझान भी बहुत उत्साहित करने वाले हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन पाठकों की तादाद में हो रहे इजाफे से राजस्व में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, खासतौर पर इस चुनावी वर्ष में। ऐसे में राजस्व वृद्धि दोबारा 7 से 9 फीसदी के स्तर पर वापस आ सकती है।

उम्मीद की जा सकती है कि आईआरएस 2020 समाचार पत्रों के कारोबार के लिए और बेहतर साबित होगा।

कानाफूसी

कर्ज माफी की पहेली

मध्य प्रदेश में कृषि ऋण माफी लंबे समय से चुनावी मुद्दा बनी हुई है। एक ओर कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने 21 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ कर दिया है तो वहीं भाजपा का दावा है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है। पिछले दिनों एक बार फिर इस पहेली में नया मोड़ आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान मंच से ही इस योजना के कुछ लाभार्थियों के नाम की घोषणा कर दी। इनमें से दो नाम बहुत खास थे। एक नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई रोहित सिंह का था तो दूसरा उनके चाचा के बेटे निरंजन सिंह का। गांधी ने दावा किया कि इन दोनों लोगों का भी कर्ज माफ किया गया है। हालांकि चौहान ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने कर्ज माफी का फार्म ही नहीं भरा तो कर्ज कैसे माफ कर दिया गया? चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्ज माफी के नाम पर कृषि विभागों के दस्तावेज पेश कर रही है जबकि उसे बैंकों की ओर से दी गई सूची जारी करनी चाहिए जिसमें कर्ज माफी की राशि और किसानों का ब्योरा हो।

आपका पक्ष

भारत का परमाणु संपन्न देश होना

विज्ञान और प्रद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हर सा 11 मई को नैशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण के बाद देश ने अपना नाम परमाणु संपन्न देशों में दर्ज करा लिया। इस उपलब्धि के बाद देश ने स्पष्ट कर दिया कि भारत गैर परमाणु देशों पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा और युद्ध के दौरान देश कभी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। इस ऐतिहासिक घटना के बाद सही मायने में देश ने दुनिया के सामने विज्ञान, तकनीक और अपनी प्रौद्योगिकी का लोहा मनवाया। जहां तक देश की रक्षा तकनीक की बात है तो भारत ने अपने दम पर पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि जैसी मिसाइल विकसित की हैं जो

पोखरण में 11 और 13 मई को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था

परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं और लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 1 के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड एक विमान वाहक पोत बना रही है। यह भारत में निर्मित होने वाला पहला विमानवाहक पोत होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हर महीने विभिन्न उपग्रह परीक्षण की वजह से सुर्खियों में रहता है। वर्ष 2017 में उसने एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपनी क्षमता का दुनियाभर को अहसास करा दिया था। इन उपलब्धियों के बावजूद देश को अभी अन्य तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी कुछ करने की जरूरत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 126 देशों की सूची में भारत 57वें स्थान पर है। आज भी भारत को स्वदेशी वस्तुओं की तकनीकी खामियों की वजह से महंगी विदेशी तकनीक पर भरोसा करना पड़ता है। इस पर विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती है। भारत में उन्नतशील प्रौद्योगिकी देश बनने की पूरी क्षमता है बशर्ते सरकार और शिक्षा संस्थान स्पष्ट नीतियां बनाकर इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करें।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

राजनीतिक बयानों का गिरता स्तर

देश में राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। राजनेता बगैर सोचे-समझे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले वे यह नहीं सोचते हैं कि इससे उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो उनके भाषण सुन रहे हैं। एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कह दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद उनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वह अन्य नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं।

मनीषा मेहलावत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।